

दि कर्मिक पोस्ट

Global
School Of
Excellence,
Obedullaganj

वर्ष : 9, अंक : 26

(प्रति बुधवार), इन्दौर, 14 फरवरी 2024 से 20 फरवरी 2024

पेज : 8

कीमत : 3 रुपये

देश में 7,506 वर्ग किलोमीटर वन भूमि पर हुआ अतिक्रमण, एनजीटी में मामले पर सुनवाई

नई दिल्ली। भारत में वन भूमि पर बड़े पैमाने पर हो रहे अतिक्रमण का मुद्दा नौ फरवरी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में उठाया गया है। गौरतलब है कि पांच फरवरी 2024 को दक्कन हेराल्ड में प्रकाशित एक खबर के आधार पर यह एनजीटी के समक्ष यह मामला उठाया गया है। इस रिपोर्ट में देश भर में वन भूमि पर बड़े पैमाने पर हुए अतिक्रमण पर प्रकाश डाला गया है। खबर के मुताबिक सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि देश में दिल्ली से करीब पांच गुणा अधिक वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि देश में कुल 7,75,288 वर्ग किलोमीटर वन भूमि में से 7,506.33 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर अतिक्रमण हुआ है। हालांकि अधिकारियों ने इस मामले पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इस अतिक्रमण वन क्षेत्र का करीब 56 फीसदी हिस्सा असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) के ओर से पेश वकील ने अदालत को सूचित किया है कि चूंकि इस मामले में कई राज्य सरकारें शामिल हैं, इसलिए मंत्रालय ने उन सरकारों से उचित कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही उन्होंने पर्यावरण मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाइयों का विवरण देते हुए प्रतिक्रिया देने के लिए अदालत से कुछ समय मांगा है। चूंकि यह मुद्दा देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा है, इसलिए अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यावरण और वन के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिवों को प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 19 अप्रैल 2024 को होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) को यह जांचने का निर्देश दिया है कि क्या मेसर्स इंडियन पोटाश लिमिटेड सिंचाई के लिए उपचारित औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट जल का उपयोग कर रहा है। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी तरह का उपचारित अपशिष्ट, चाहे वह उद्योगों से निकल रहा हो या घरों से, कंपनी द्वारा सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है और इसे बरसाती पानी की निकासी के लिए बनाई नालियों में नहीं जाने दिया जाता। एनजीटी ने यूपीपीसीबी को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि मुजफ्फरनगर में उद्योगों से निकलने वाले दूषित जल को बरसाती नालों में न छोड़ा जाए। साथ ही उन्हें नदी तक पहुंचने वाले पानी की गुणवत्ता की निगरानी करने का भी निर्देश दिया गया है। कोर्ट का यह भी कहना है कि इन नियमों का



उल्लंघन करने वाले किसी भी उद्योग के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना है कि कोयले से उत्पन्न फ्लाई ऐश में हानिकारक भारी धातुएं होती हैं और ऐसे में इसका उपयोग किसी भी कृषि क्षेत्र को भरने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय, इसका उपयोग सीमेंट या ईंट बनाने वाले उद्योगों द्वारा किया जाना चाहिए। कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से छह महीनों के भीतर ऐसे सभी उद्योगों से निकलने वाली फ्लाई ऐश के उचित निपटान के लिए योजना को अंतिम रूप देकर एक रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा है, जिनसे वायु प्रदूषण हो रहा है।

सौंदर्यीकरण पर खर्च होंगे साढ़े 3 करोड़

इंदौर एमआर-10 कुम्हेड़ी कांकड़ में बन रहे इंटर स्टेट बस टर्मिनल (आइएसबीटी) के निर्माण का काम धीमी गति से चल रहा है। अब भी करीब 4 महीने का समय लगेगा। आइडीए ने बाहरी सौंदर्यीकरण के लिए अब साढ़े 3 करोड़ का टेंडर जारी किया है। एयरपोर्ट की तर्ज पर लुक देते हुए आइएसबीटी का निर्माण किया जा रहा है। पूरा बस स्टैंड वातानुकूलित रहेगा। अब तक करीब 80 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। शोड डालने का काम काफी समय बाद भी पूरा नहीं हुआ है। आइडीए ने इलेक्ट्रिकेशन, एयर कंडिशनिंग, फाउनटेंन आदि काम के लिए साढ़े 3 करोड़ का टेंडर जारी किया है। आइडीए अध्यक्ष जयपालसिंह चावड़ा के मुताबिक, काम तेजी से चल रहा है, लेकिन पूरा होने में करीब 4 महीने लगने की संभावना है। इधर, नायता मुंडला का आइएसबीटी बनकर तैयार है। कलेक्टर आशीष सिंह ने जल्द बस स्टैंड शुरू करने के लिए निर्देशित किया है। बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए आरई 2 सड़क बनाई जा रही है, लेकिन अभी उसका काम पूरा नहीं हो पाया है।

स्वच्छता ने बनाया मुरीद

इंदौर. राजबाड़ा देशवासियों ही नहीं, बल्कि विदेशियों के मन भी बसा है। बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी राजबाड़ा की सुंदर छवि को अपने मोबाइल में कैद करते हैं। जगह-जगह सेल्फी लेते और फोटो क्लिक कराते हैं। पिछले 5 महीनों में लाखों की संख्या में भारतीय नागरिकों और करीब 200 विदेशियों ने राजबाड़ा और लालबाग का भ्रमण किया है।

राजबाड़ा के डिप्टी डायरेक्टर प्रकाश परांजपे ने बताया, हर दिन 1 हजार से 1200 के बीच में पर्यटक राजबाड़ा का भ्रमण करने आते हैं। लालबाग में रिनोवेशन का काम होने के कारण अभी वहां जाने वाले पर्यटकों की संख्या कम है। लालबाग पैलेस में काम कराने के लिए करीब 9.45 लाख रुपए मंजूर हुए थे, जिसमें करीब 7 करोड़ रुपए के काम हो चुके हैं। बची राशि होल्ड पर रखी गई, जिससे क्षतिग्रस्त बाउंड्रीवॉल के अलावा और काम किए जाएंगे। हरियाणा से आए अभिषेक चौहान ने बताया, फैमिली के साथ बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन आए थे। जिस होटल में ठहरे थे, वहां से बताया गया कि राजबाड़ा और 56 दुकान विजिट जरूर कीजिए। रात को 56 दुकान घूमने गए और इसके बाद रविवार को राजबाड़ा घूमने आए हैं। यहां का दृश्य बहुत ही अच्छा है। यहां पुरानी धरोहर को संजोकर रखा गया है, यह बड़ी बात है।

यहां जैसी स्वच्छता और कहीं नहीं - विशाखा शर्मा ने कहा, ऐसी स्वच्छता हमें किसी और शहर में देखने को नहीं मिलती है। यहां के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक हैं। 56 दुकान में खाने के बाद टिशू पेपर मांगा तो यह कहकर मना कर दिया कि जगह-जगह यूज करके इसे फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी। पहली बार हम लोग इंदौर आए हैं। डायरेक्टर ने माना कि पर्यटकों को गाइड करने की व्यवस्था नहीं है। लालबाग में ऑडियो गाइड इंस्टाल हो चुका है। राजबाड़ा पर भी इस सिस्टम को लागू करने की योजना है। राजबाड़ा का कुछ ही हिस्सा खोला गया है। विकलांगों के लिए लिफ्ट जैसी सुविधाएं हो जाएंगी। इसके बाद पर्यटकों को स्कैन करके गाइड की सुविधा मिलेगी।

जंगलों का होता विनाश वातावरण में उत्सर्जित कर रहा है सालाना 217 मेगाग्राम पारा

नई दिल्ली। दुनिया भर में काटे जा रहे जंगलों की वजह से हर साल करीब 217 मेगाग्राम पारा वातवरण में मुक्त हो रहा है। यह आंकड़ा कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुनिया में हर साल इंसानों द्वारा जितना पारा उत्सर्जित किया जाता है, यह इसका 10 फीसदी है। जो न केवल इंसानी स्वास्थ्य बल्कि पर्यावरण के लिए भी एक बड़ा खतरा है। यह जानकारी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन में सामने आई है, जिसके नतीजे आठ फरवरी 2024 को जर्नल एनवायरनमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रकाशित हुए हैं। बता दें कि मर्करी यानी पारा एक न्यूरोटॉक्सिन है, जिसकी बहुत थोड़ी मात्रा भी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है।

देखा जाए तो पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों का ध्यान काटे जा रहे जंगलों की वजह से पर्यावरण में मुक्त हो रही कार्बन डाइऑक्साइड पर केंद्रित रहा है। लेकिन पारा जिसकी तुलनात्मक रूप से कम मात्रा वातावरण में मौजूद है, उसपर उतना ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इस रिसर्च से पता चला है कि वनों का होता विनाश भी बड़ी मात्रा में पारे के होते उत्सर्जन के लिए जिम्मेवार है। दुनिया भर में मौजूद पेड़-पौधे और वनस्पतियां जैसे अमेजन के वर्षावन और अफ्रीकी सवाना, पारा जैसे जहरीले प्रदूषकों को अवशोषित करके हवा को साफ करने में मदद करते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि जिस तरह से इन जंगलों का विनाश किया जा रहा है वो दर जाती रहती है या पहले से तेज हो जाती है तो पारा उत्सर्जन अवशोषित होने के बजाय बढ़ता रहेगा। रिसर्च से पता चला है कि अमेजन वर्षावन पारे को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो भूमि पर अवशोषित किए जा रहे पारे में करीब 30 फीसदी का योगदान देते हैं। ऐसे में यदि इन जंगलों को काटने से बचाया जाए तो यह पारे से हो रहे प्रदूषण को कम करने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी चेताया है कि यदि अमेजन वर्षा वनों में जंगलों का होता विनाश मौजूदा दर से जारी रहता है तो 2050 तक इस क्षेत्र में होता पारे का शुद्ध उत्सर्जन बढ़कर सालाना 153 मेगाग्राम तक पहुंच जाएगा। बता दें कि कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही पेड़-पौधों की पत्तियां वातावरण से पारे को अवशोषित करती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के विपरीत, पारा पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं होता। ऐसे में आमतौर पर यह पत्तियों में तब तक बना रहता है जब तक वो जमीन पर नहीं गिरती, जहां मिट्टी इसे अवशोषित कर लेती है। वहीं पानी में मिलने के बाद पारा लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी समस्या बन जाता है, जहां सूक्ष्म जीव इसे मिथाइलमरकरी में बदल देते हैं, जो एक न्यूरोटॉक्सिन होता है। जब मछलियां इस मिथाइलमरकरी का सेवन करती हैं तो यह इनके जरिए लोगों के शरीर में पहुंच सकता है।

स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है पारा- पारा के बारे में बता दें कि यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक तत्व है, जो हवा, पानी और मिट्टी में पाया जाता है। हालांकि इसके संपर्क में आने से स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान हो सकता है। यह पाचन, तंत्रिका तंत्र, फेफड़ों, गुर्दे, त्वचा और प्रतिरक्षा प्रणाली पर बुरा असर डाल सकता है। इतना ही नहीं इसका संपर्क गर्भस्थ शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास को भी प्रभावित कर सकता है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2015 में इंसानों द्वारा किया जा रहा पारे का उत्सर्जन बढ़कर 2,220 टन पर पहुंच गया था। जो 2010 की तुलना में करीब 20 फीसदी ज्यादा है। जर्नल पनास नेक्सस में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार हर साल करीब 1,833.3 मेगाग्राम पारे का उत्सर्जन हो रहा है। इसमें से अधिकांश उत्सर्जन गैर-लौह धातुओं को गलाने और पिघलाने से जुड़ा है। इस अध्ययन के मुताबिक पारे के कुल वैश्विक उत्सर्जन का करीब 47.1 फीसदी हिस्सा यानी 864.2 मेगाग्राम इसके अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा है। वहीं यदि देशों द्वारा उत्सर्जित किए जा रहे पारे की मात्रा को देखें तो चीन हर साल करीब 546.1 मेगाग्राम पारा उत्सर्जित कर रहा है। इसके बाद उप-सहारा अफ्रीका 291.8 मेगाग्राम और दक्षिण अमेरिका 291.3 मेगाग्राम पारे के उत्सर्जन के लिए जिम्मेवार है। बता दें कि इससे पहले भी पारे को लेकर कई अध्ययन किए गए हैं लेकिन ज्यादातर मामलों में जीवाश्म ईंधन दहन, सोने के खनन, और धातुओं को गलाने के लिए पारे का होता इस्तेमाल जैसे औद्योगिक स्रोतों पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है। गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर पारे के हानिकारक प्रभावों को देखते हुए 2013 में इसकी रोकथाम के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि की गई थी, जिसे मिनामाता कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। यह संधि देशों द्वारा किए जा रहे पारे के उत्सर्जन को कम करने का आह्वान करती है।

भारत ने भी 2018 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अब तक 141 देश इस संधि को अपना चुके हैं। हालांकि इसके बावजूद अभी भी दुनिया में बड़े पैमाने पर पारे का उपयोग जारी है, जो इसके बढ़ते प्रदूषण की वजह बन रहा है। आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एजेंसी ने 2018 में 22 देशों के 300 से ज्यादा उत्पादों में पारे की जांच की थी। इस जांच में कई उत्पादों में सीमा से 10 गुणा तक ज्यादा पारे के इस्तेमाल की बात सामने आई थी। वहीं एक अन्य अध्ययन में भारत में भी क्रीमों में इसके मिलने की बात सामने आई थी। टॉक्सिक लिंक द्वारा भारत से लिए नमूनों में मर्करी का स्तर 48 पीपीएम से 113,000 पीपीएम तक मिला था। शोधकर्ताओं के मुताबिक यदि वैश्विक स्तर पर वनों की बहाली पर ध्यान दिया जाए तो वातावरण से अवशोषित किए जा रहे पारे की मात्रा में पांच फीसदी की वृद्धि की जा सकती है। ऐसे में यह जंगल जो हमारे लिए अनगिनत तरीकों से फायदेमंद हैं वो पारे के बढ़ते प्रदूषण से निजात दिलाने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। सही नीतियां इनके विनाश को रोक सकती हैं। जो न केवल हमारे आज बल्कि आने वाली नस्लों को बेहतर भविष्य देने में मददगार होगा।

महत्वपूर्ण केमिकल एथिलीन में बदल जाएगी ग्रीनहाउस गैस, इंजीनियरों ने खोजा तरीका



मुंबई। अमेरिका स्थित सिनसिनाटी विश्वविद्यालय के इंजीनियरों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को मूल्यवान उत्पादों में बदलने का एक किफायती और कुशल तरीका खोज निकाला है। शोध में कहा गया है कि सिनसिनाटी विश्वविद्यालय (यूसी) के केमिकल इंजीनियरिंग लैब में, एसोसिएट प्रोफेसर जिंगजी वू और उनकी टीम ने एक संशोधित तांबे के उत्प्रेरक की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रोकेमिकल में बदलाव कर इसे एथिलीन में बदल दिया है। एथिलीन को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण केमिकल या रसायन माना गया है। यह निश्चित रूप से सबसे अधिक उत्पादित रसायनों में से एक है, जिसका उपयोग वस्त्रों, एंटीफ्रीज से लेकर विनाइल तक हर चीज में किया जाता है। केमिकल उद्योग ने 2022 में 22.5 करोड़ मीट्रिक टन एथिलीन का उत्पादन किया।

शोध के हवाले से वू ने कहा कि यह प्रक्रिया जीवाश्म ईंधन के बजाय ग्रीन ऊर्जा के माध्यम से एथिलीन का उत्पादन करती है। साथ ही इससे वायुमंडल से कार्बन हटाने का अतिरिक्त फायदा भी मिलता है। नेचर केमिकल इंजीनियरिंग पत्रिका में प्रकाशित शोध के मुताबिक, दुनिया भर में एथिलीन एक अहम केमिकल है, लेकिन इसके उत्पादन के लिए पारंपरिक भाप-क्रैकिंग प्रक्रिया भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती है। शोध में कहा गया है कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भर रहने के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड को फीडस्टॉक के रूप में उपयोग करके, प्रभावी ढंग से

कार्बन डाइऑक्साइड की रीसाइक्लिंग की जा सकती है। यहां बताते चलें कि किसी मशीन या औद्योगिक प्रक्रिया की आपूर्ति या ईंधन के लिए कच्चे माल को फीडस्टॉक के रूप में जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रोकेमिकल रूपांतरण के पहले कार्बनिक उत्पाद, एथिलीन और इथेनॉल उत्पन्न होते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि संशोधित तांबे के उत्प्रेरक का उपयोग करने से अधिक एथिलीन उत्पन्न होती है। मुख्य शोधकर्ता ली ने कहा, हमारा शोध इलेक्ट्रोकेमिकल सीओ₂ कटौती के दौरान एथिलीन और इथेनॉल के बीच अंतर पर अहम जानकारी प्रदान करता है। वू ने कहा, इससे एथिलीन में 50 फीसदी की वृद्धि होती है। उन्होंने आगे कहा हमारा लक्ष्य कई उत्पादों के बजाय एक ही उत्पाद का उत्पादन करना है। ली ने बताया कि अगला कदम प्रक्रिया को और अधिक व्यावसायिक रूप से कुशल बनाना है। कुछ समय बाद एथिलीन में बदलने की प्रणाली कुशलता खो देती है क्योंकि प्रतिक्रिया के अन्य उत्पाद जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तांबे के उत्प्रेरक पर बनने लगते हैं। ली ने कहा, व्यावसायिक तौर पर उपयोग के लिए इलेक्ट्रोड स्थिरता में सुधार किया जाना चाहिए। हमारा अगला लक्ष्य स्थिरता को बढ़ाना और इसके संचालन को 1,000 से 1,00,000 घंटे तक बढ़ाना है। वू ने कहा कि ये नई तकनीकें रासायनिक उद्योग को ग्रीन और अधिक ऊर्जा कुशल बनाने में मदद करेंगी। वू ने बताया, हमारा मुख्य उद्देश्य नवीकरणीय बिजली और टिकाऊ फीडस्टॉक का उपयोग करके रासायनिक उत्पादन को डीकार्बोनाइज्ड करना है। कार्बन डाइऑक्साइड को एथिलीन में विद्युतीकृत करना रासायनिक क्षेत्र को डीकार्बोनाइजिंग करने में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में देखा जा सकता है।



मुख्यमंत्री डॉ. यादव से मिले पद्मश्री सतेंद्र सिंह

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से आज शाम समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास में पद्मश्री से सम्मानित दिव्यांग स्वीमर श्री सतेंद्र सिंह लोहिया ने भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री सत्येंद्र सिंह को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री के लिए चयनित होने के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दीं। उल्लेखनीय है कि श्री सत्येंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक उपलब्धियां अर्जित कर चुके हैं। इन्होंने इंग्लिश चैनल सहित अनेक बड़े महासागर साहसपूर्वक और सफलतापूर्वक तैरकर पार कर चुके हैं। इनकी उपलब्धियां के लिए अनेक सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका

नगर निगम इन्दौर और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बदहाल कर दिया क्षिप्रा नदी को



इन्दौर। क्षिप्रा नदी के क्षरण को लेकर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत की गई है। इसमें कहा गया कि 2001 से क्षिप्रा नदी में तेजी से गिरावट आई है। 2010-11 के बाद मानसून सीजन के पहले और बाद में क्षिप्रा नदी लगभग सूखने लगी। प्रदूषण के कारण क्षिप्रा और सहायक नदियों की जल गुणवत्ता और भूजल घटने से प्रवाह प्रभावित हुआ। उज्जैन के साथ ही इन्दौर नगर निगम के सिवरेज नेटवर्क ने सबसे ज्यादा क्षिप्रा को नुकसान पहुंचाया है। इसी के साथ उज्जैन, इन्दौर और देवास ने पूरे भौगोलिक क्षेत्र के लिए सिवरेज नेटवर्क की योजना नहीं बनाई।

क्षिप्रा नदी की स्थिति पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने चौंकाने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नगरीय निकायों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की लापरवाही से क्षिप्रा नदी प्रदूषित और बदहाल हुई है। विभिन्न विभागों ने अनेक स्तर पर जिम्मेदारी का पालन नहीं किया है। जिम्मेदार विभागों ने अपनी वाहवाही के लिए सेवा स्तर के मानदंड लक्ष्यों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया। रिपोर्ट में बताया गया कि उज्जैन में 1990 में क्षिप्रा का प्रवाह तुलनात्मक रूप से बेहतर था। प्रदूषण के साथ

ही सहायक नदियों की जल गुणवत्ता और नदी प्रवाह क्षेत्र में भूजल घटने से क्षिप्रा का प्रवाह प्रभावित हुआ है। औद्योगिक कचरे का उपचार अपर्याप्त रहा। वर्षा जल के प्रवाह का उपयोग क्षेत्र में जल वृद्धि करने में नहीं किया गया। अल्प प्रवाह की अवधि में क्षिप्रा नदी में पानी उपलब्ध कराने का प्रावधान तो किया गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया। सीएजी ने रिपोर्ट में सुधार को लेकर कई अनुशंसा करते हुए नगर स्वच्छता योजना को नदी से जोड़ने के लिए निर्देश दिये इसके अलावा सिवरेज नेटवर्क पूरी तरह विकसित करने और अतिक्रमण हटाने को लेकर विशेष सुझाव दिये इसी के साथ पर्याप्त वृक्षारोपण भी किए जाने की अनुशंसा की।

कान्ह, क्षिप्रा नदी के फ्लड प्लेन जोन में अतिक्रमण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच में यह भी देखा कि उद्योग या तो ईटीपी के बिना चल रहे थे। स्थानीय निकायों ने फ्लड प्लेन जोन में विनियमन के संबंध में दिशानिर्देश जारी नहीं किए थे। कान्ह और क्षिप्रा नदी के फ्लड प्लेन जोन में व्यापक अतिक्रमण है। नदी तट विकास कार्य सही तरीके से नहीं किए गए। पौधारोपण की योजना अप्रभावी पाई गई।

उद्योगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के इन्दौर, देवास और उज्जैन क्षेत्रीय कार्यालयों ने वैध स्थापना सहमति और संचालन सहमति के साथ उद्योगों की स्थापना और संचालन, नवीनीकरण और स्वीकृति संबंधी सहमति 46 से 615 दिन के विलंब से दी। बिना सहमति के उद्योग चल रहे थे, क्योंकि उनकी संचालन सहमति की वैधता समाप्त हो गई थी और ऐसे उद्योगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

493 दिन से साइकिल यात्रा पर है पर्यावरण प्रेमी, कहा- ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं

निवाड़ी भारत में घटते वन क्षेत्र का संरक्षण पुनर्विकरण वन क्षेत्र में वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तन के वैश्विक खतरे को देखते हुए यह जागरण अभियान को रोबिन सिंह निवासी इटावा मात्र एक व्यक्ति है जो अकेले साइकिल द्वारा संपूर्ण भारत में यात्रा द्वारा कर रहे हैं। इस भ्रमण



को आज 493 दिवस पूरी हो चुके हैं। इसी कड़ी में वो रविवार को निवाड़ी पहुंचे।

रोबिन सिंह पुत्र विष्णु सिंह ग्राम पिपरोली जनपद इटावा द्वारा जन जागरण अभियान पूरे भारत वर्ष में साइकिल यात्रा के माध्यम से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए संदेश दिया जा रहा है। रोबिन ने बताया कि भारत में घटते वन क्षेत्र का संरक्षण एवं जलवायु के

परिवर्तन की खतरे को देखते हुए जन जागरण अभियान साइकिल द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सभी भारतवासियों को जागरूक कर रहे हैं। 6 अक्टूबर 2022 को कन्याकुमारी (तमिलनाडु) से इस यात्रा को प्रारंभ किया। उन्होंने बताया कि अभी तक उन्होंने 493 दिन की यात्रा कर 29000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। इसके साथ ही वो अब 24वें राज्य मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं। 11 मार्च को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस अभियान का प्रथम चरण का समापन होगा।

10.8 लाख का पैकेज छोड़ पर्यावरण संरक्षण के लिए पैदल निकले आशुतोष

इन्दौर कहने को तो उनकी उम्र महज 25 वर्ष है, परंतु हौसला और हिम्मत पहाड़ जैसी। ये हैं आशुतोष पांडे, जो 22 दिसंबर 2022 को पर्यावरण संरक्षण के लिए पैदल ही भारत यात्रा पर निकल पड़े। उत्तर प्रदेश से चलकर ये बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत 13 राज्यों से होते हुए इन्दौर पहुंचे हैं। इन दिनों इनका ठिकाना इन्दौर है। अब तक आशुतोष 21 राज्य, 75 जिले, 1700 गांवों से लोगों को जागरूक करते हुए जा रहे हैं। पर्यावरण और प्रकृति के प्रति इनका जुनून ऐसा है कि ये 90 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन वाली नौकरी छोड़कर भारत दर्शन यात्रा पर निकले हैं। आशुतोष के मन में प्रकृति संरक्षण का संदेश देने का यह विचार कहां से आया? यह पूछने पर वे नईदुनिया से बातचीत में कहते हैं- कोरोना काल में आक्सीजन की पूर्ति न होने से मेरे एक प्रिय मित्र की मृत्यु हो गई थी। उस क्षण लगा कि यदि आक्सीजन नहीं, प्रकृति नहीं, पर्यावरण नहीं है तो फिर हम सबका जीवन क्षणभंगुर है। यही विचार मन को मथता रहा और एक दिन ऐसा भी आया जब 10.80 लाख रुपये सालाना की नौकरी छोड़कर पर्यावरण बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रण लिया और पैदल भारत यात्रा शुरू कर दी।